vinetur

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बेलें उखाड़ने की सहायता के लिए 1 करोड़ यूरो मंजूर किए

बेलें उखाड़ने की योजना में उम्मीद से अधिक मांग के बाद उत्पादकों के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित करने को 1 करोड़ यूरो मंजूर

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



फ्रांस की नेशनल असेंबली ने गुरुवार, 12 नवंबर को 1 करोड़ यूरो के संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उन अंगूर उत्पादकों की सहायता के लिए वित्तपोषण बढ़ाना था जो अपनी बेलें उखाड़ रहे हैं। यह कदम 2025 के अंत में घोषित सहायता योजना की उम्मीद से अधिक मांग पूरी करने के लिए उठाया गया।

संशोधन संख्या 105 को 2026 के साल-अंत बजट समायोजन विधेयक पर बहस के दौरान अपनाया गया। असेंबली के आधिकारिक नतीजों के अनुसार, इसके पक्ष में 45 और विरोध में 4 वोट पड़े ; मतदान में 64 सांसदों ने हिस्सा लिया।

संशोधन पेश करने वाले सांसद Jean-René Cazeneuve ने सदन से कहा कि सरकार द्वारा घोषित बेलें उखाड़ने की प्रोत्साहन राशि को “सुनिश्चित” करने के लिए यह धन आवश्यक था। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कृषि और कृषि निर्यात

का बड़ा हिस्सा रहे वाइन क्षेत्र पर निर्यात शुल्क, कई वर्षों से जारी जलवायु-संबंधी संकटों और खपत में गिरावट का असर पड़ा है। उनके मुताबिक, योजना के तहत प्रतिबद्धताएं शुरुआती अनुमान से अधिक होने के कारण 1 करोड़ यूरो का इस्तेमाल किया जाएगा।

यह उपाय उस राशि से संबंधित है जिसे फ्रांसीसी सांसदों ने prime à l'arrachage कहा—यानी बेलें उखाड़ने वाले उत्पादकों को दिया जाने वाला भुगतान। ऐसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल आम तौर पर उन क्षेत्रों में अंगूर के बागों का रकबा घटाने के लिए किया जाता है जहां उत्पादन को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। फ्रांस में इस मुद्दे पर ध्यान बढ़ा है, क्योंकि कुछ वाइन क्षेत्रों को कमजोर मांग, निर्यात पर दबाव और बार-बार मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने इस संशोधन का समर्थन किया। सार्वजनिक कार्रवाई और लेखा मंत्री David Amiel ने सांसदों से कहा कि वे प्रस्ताव के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हालिया दौर को बेहद कठिन बताते हुए वाइन उद्योग के लिए यह कदम जरूरी है।

वित्त समिति के सामान्य प्रतिवेदक Philippe Juvin ने कहा कि संशोधन देर से दाखिल किया गया था, इसलिए समिति ने इसकी जांच नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वे इसके उद्देश्य को समझते हैं और बताया कि कृषि, खाद्य, वानिकी और ग्रामीण मामलों के बजट मिशन का कुल बजट लगभग 3.6 अरब यूरो था। सरकार का रुख सामने आने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या इस मद से 1 करोड़ यूरो जुटाए जा सकते हैं। सरकार का समर्थन सुनने के बाद असेंबली ने मतदान कराया।

यह चर्चा साल-अंत के वित्त विधेयक पर चली लंबी बैठक के दौरान हुई। यह विधेयक 2026 के वित्त वर्ष के अंत से पहले खर्च और विनियोगों में संशोधन करता है। इसी बैठक में सांसदों ने सरकार समर्थित एक अन्य कृषि उपाय को भी मंजूरी दी : कृषि या वानिकी कार्यों के लिए गैर-सड़क डीज़ल खरीदने वाली कंपनियों को दी जाने वाली असाधारण सहायता का वित्तपोषण पूरा करने के लिए 1.2 करोड़ यूरो का संशोधन। इस व्यापक संदर्भ से पता चला कि बजट पर बहस के दौरान कृषि सहायता ऐसे मुद्दों में शामिल थी जिन पर विभिन्न दलों का ध्यान गया।

बेलों से संबंधित संशोधन को मिले समर्थन के अंतर ने इसे खास बना दिया। इसी बैठक में चर्चा किए गए कई अन्य संशोधन खारिज कर दिए गए थे, अक्सर सरकार और वित्त समिति की नकारात्मक राय के बाद। हालांकि, वाइन से जुड़े इस प्रस्ताव का सरकार ने समर्थन किया और प्रतिवेदक ने इसका विरोध नहीं किया, जिससे सदन में इसे व्यापक समर्थन मिला।

पेय उद्योग के लिए यह मतदान फ्रांस की संसदीय प्रक्रिया से आगे भी मायने रख सकता है। फ्रांस दुनिया के सबसे बड़े वाइन उत्पादकों में शामिल है और अंगूर के बागों के पुनर्गठन से अंगूर की आपूर्ति, उत्पादकों की वित्तीय स्थिति और लंबे समय से बाजार के दबाव का सामना कर रहे क्षेत्रों में बदलाव की गति प्रभावित हो सकती है। अगर कम खपत, व्यापार संबंधी दबाव और जलवायु से हुए नुकसान उत्पादकों पर असर डालते रहे, तो बेलें उखाड़ने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक धन से अधिकारियों को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।

मतदान का अर्थ यह नहीं है कि यह उपाय अपने-आप कानून बन गया। नेशनल असेंबली के विधायी रिकॉर्ड के अनुसार, 2026 का साल-अंत बजट विधेयक संशोधन अपनाए जाने के बाद, गुरुवार 12 नवंबर को सदन में बाद में खारिज कर दिया गया। इसका मतलब है कि संसदीय प्रक्रिया के इस चरण में 1 करोड़ यूरो का आवंटन मंजूर हुआ था, लेकिन इसका अंतिम भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापक बजट कानून की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है।